गया है। यह नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का एक अंग है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 16.2 लाख एकड मुहैया करने के उद्देश्य से स्थल तथा सेवा योजनाओं के लिए 485 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश पर भी विचार किया गया है। आवास क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों को प्रति-वर्ष जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम के ऋण भी उपलब्ध कराये जाते हैं। जीवन बीमा निगम सहकारी आवास क्षेत्र के लिए भी ऋण सहायता देता है।

2. केन्द्रीय क्षेत्र में, बागान मजदूर आवास हेतु वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ रूपये परिव्यय की योजना है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु औसतन लगभग 30 करोड़ का नियतन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस योजना में सामान्य पूल रिहायशी एवं कार्यालय वास के लिए 142 करोड़ रूपये के परिव्यय की भी व्यवस्था है।

3. आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ने जो भारत सरकार का एक उद्यम है, योजना अवधि के दौरान 600 करोड़ रूपये के निवेश पर विचार किया है जिस का 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए होगा।

4. आवास के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1981 के भारतीय रिजर्व बैंक मार्ग निदेशनों के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जिसमें से 66 करोड़ रूपया बैंकों ने बांट दिया है।

Conference of Revenue Ministers of States

*116. SHRI K. T. KOSALRAM:
SHRI RAMAVATAR SHASTRI:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the decisions taken at the recent Conference of State Revenue Ministers held in New Delhi for speedy implementation of land reforms and distribution of surplus lands; and

(b) the action proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BALESHWAR RAM): (a) State Governments have been requested to expedite distribution of ceiling surplus land and to this end, take steps to secure quicker disposal of cases pending in courts. They have also been requested to adopt various measures for updating land records.

(b) Implementation of land reforms is the responsibility of the State Governments who are taking appropriate steps on the lines of the suggestions made at the Conference.

Steps to Increase Food Production

*117. SHRI H. N. NANJE GOWDA:
SHRI K. LAKAPPA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether according to a study conducted by the International Food Policy Research Institute (IFPRI), India's foodgrain production is unstable despite impressive increases in foodgrains;

(b) whether it is also a fact that due to unprecedented floods and drought in the country, the food output remains unstable despite increases; and

(c) if so, steps taken/proposed to be taken to stabilise the increased food output in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND

RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir. A study entitled "Instability in Indian Foodgrains Production" by Peter B. R. Hazell at the International Food Policy Research Institute, has pointed to the unstable nature of foodgrain production in the country despite impressive increases. The Study however clearly underlines that "A large part of the increase in production instability probably has to be accepted as a necesary consequence of successful agricultural growth".

(b) Due to effects of droughts and floods from time to time food production is affected.

(c) It has been the constant endeavour of the Government to increase and stabilise the production of foodgrains. The various measures taken in this direction are as follows:—

(i) Extending irrigation facilities to unirrigated areas and efficient utilization of the available water resources;

(ii) Introduction of high-yielding and short duration varieties of crops;

(iii) Adoption of improved technology including water harvesting and moisture conservation, for cultivation of crops in drylands and under rain-fed conditions;

(iv) Timely availability of various farm inputs to the farmers;

(v) Increased and balanced use of fertilizers;

(vi) Regular monitoring of diesel and electric power supplies for irrigation purposes;

(vii) Intensive extension efforts to bring about transfer of technology at the farm level;

(viii) Extension of credit facilities to the farmers; and

(ix) Implementation of contingency production plans to mitigate the adverse effects of drought and floods.

एशियाड टिकटों की बिचौलियों के माध्यम से बिक्री

***118. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड 1982 की टिकटों की बिक्री या वितरण समुचित नहीं था और टिकटें सीधी जनता को नहीं मिलीं अपितु ये बिचौलियों के माध्यम से मिलीं जिन्होंने इन्हें कालाबाजार में बेचना आरम्भ कर दिया है और लोगों को ये टिकटें प्राप्त करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने का है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नौवें एशियाड खेल, 1982 की टिकटें भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भारत के 91 नगरों में तथा एअर इंडिया और इण्डियन एअरलाइन्स के माध्यम से बाहर के 35 देशों में 129 बिक्री केन्द्रों पर उचित और सुव्यवस्थित ढंग से बेची गई हैं। बिक्री केन्द्रों पर बेरिकेड्डों की सहायता से ठीक तरह से लाइन बनाने तथा पेय जल जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रबन्ध किए गए थे। भारत में टिकटों की बिक्री का भिन्न-भिन्न समय इस दृष्टि से रखा गया ताकि जनता अपनी मरजी की टिकटें ले सके। भारत अथवा विदेश के किसी भी टिकट बिक्री केन्द्र से टिकटों की काला-बाजारी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।